International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 7 Issue 09 Ver. I ||September 2018 || PP 76-80

राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा का अवलोकात्मक अध्ययन

डॉ दीप कुमार श्रीवास्तव
एसोसिएट प्रोफेसर रक्षा अध्ययन विभाग एस एम कॉलेज चंदौसी

सार
राष्ट्रीय सुरक्षा किसी देश की सरकार की अपने नागरिकों, अर्थव्यवस्था और अन्य संस्थानों की रक्षा करने की क्षमता है।आज, राष्ट्रीय सुरक्षा के कुछ गैर-सैन्य स्तरों में आर्थिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, मातृभूमि सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, मानव सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा शामिल हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सरकारें कूटनीति के साथ-साथ राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति सहित रणनीति पर भरोसा करती हैं।
20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सख्ती से सैन्य शक्ति और तैयारी का मामला था, लेकिन परमाणु युग की शुरुआत और शीत युद्ध के खतरों के साथ, यह स्पष्ट हो गया कि पारंपरिक सैन्य युद्ध के संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा को परिभाषित करना महत्वपूर्ण था। अतीत की बात बन जाओ। आज, अमेरिकी सरकार के नीति निर्माता कई "राष्ट्रीय प्रतिभूतियों" की मांगों को संतुलित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इनमें आर्थिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, मातृभूमि सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, मानव सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा प्रमुख हैं।
अलग-अलग एजेंसियों, संस्थानों और अभिनेताओं के एक साथ काम करने के परिणामस्वरूप सुरक्षा और सुरक्षा हासिल की जाती है। खराब समन्वय, या राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देने वाले सभी तत्वों पर विचार करने में विफलता (विशेष रूप से जो पारंपरिक सुरक्षा प्रदाताओं के बाहर हैं), अप्रभावीता, अक्षमता, साथ ही बढ़ती असुरक्षा का कारण बन सकती हैं।

कीवर्ड *अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय, सुरक्षा, राजनीतिक, संघर्ष, युद्ध, क्षमता।*

राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा

मानव सुरक्षा तत्वों ने एक व्यापक आयाम हासिल कर लिया है, क्योंकि वे सैन्य सुरक्षा से परे जाते हैं और मानवीय गरिमा के लिए खतरा पैदा करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को अपने नागरिकों की सुरक्षा और रक्षा के लिए राज्य की क्षमता के रूप में वर्णित किया गया है। मकिंडा की सुरक्षा की परिभाषा राष्ट्रीय सुरक्षा के इस दायरे में फिट बैठती है। दूसरी ओर, वैश्विक सुरक्षा प्रकृति और कई अन्य गतिविधियों, विशेष रूप से वैश्वीकरण, द्वारा राज्यों पर डाली गई आवश्यकता से विकसित हुई है। ये ऐसी मांगें हैं जिन्हें किसी भी राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र के पास अपने दम पर संभालने की क्षमता नहीं है और इसलिए राज्यों के सहयोग की मांग की जाती है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा टूटना एक वैश्विक सुरक्षा समस्या है। इसलिए, यह सभी के हित में है कि किसी भी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती को वैश्विक समस्या में बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। देशों के बीच वैश्विक अंतर्संबंध और अन्योन्याश्रितता, जिसे दुनिया ने अनुभव किया है और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से अनुभव करना जारी रखे हुए है, राज्यों के लिए यह आवश्यक बनाता है कि वे अधिक सहयोग करें और एक साथ काम करें। पारंपरिक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति अपर्याप्त रूप से सुसज्जित है। वैश्विक सुरक्षा विश्लेषकों के

अनुसार, गैर-राज्य सशस्त्र अभिनेताओं से निपटने में लचीली व्यवस्था हमेशा आवश्यक होगी। 1986 के गोल्डवाटर-निकोल्स रक्षा विभाग पुनर्गठन अधिनियम की धारा 603 के अनुसार प्रस्तुत की गई यह रिपोर्ट अद्वितीय अवसरों और खतरों के इस युग में हमारे राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति तैयार करती है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि एक सुरक्षित, अधिक समृद्ध अमेरिका के हमारे लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारी घरेलू ताकत और विदेश में हमारा नेतृत्व दोनों आवश्यक हैं।

<u>संबंधित साहित्य का अध्ययन</u>

<u>राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति रिपोर्ट</u> , द्वारा बनाई गई वार्षिक रिपोर्टसंयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने कांग्रेस को संयुक्त राज्य के राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्यों और उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयोग की जाने वाली रणनीतियों का वर्णन किया। द्वारा तैयार की गई रिपोर्टराष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी), अमेरिकी विदेश नीति , विदेशों में सैन्य और सुरक्षा प्रतिबद्धताओं और वर्तमान राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं सहित राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को आकार देने वाले मुद्दों की जांच करती है।

<u>राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस को पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 1950</u> में हैरी एस. ट्रूमैन। ट्रूमैन की रिपोर्ट ने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता पर ध्यान केंद्रित किया । इसने रोकथाम के सिद्धांत को रेखांकित किया - साम्यवाद के प्रसार का विरोध करने के लिए अमेरिकी राजनीतिक और सैन्य शक्ति का विश्वव्यापी उपयोग - जो शीत युद्ध काल के दौरान अमेरिकी विदेश नीति पर हावी था । उस समय से प्रत्येक राष्ट्रपति ने ऐसी रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं जो दिन के सबसे अधिक दबाव वाले राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों को दर्शाती हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की दिशा का संकेत देती हैं।

<u>1947 के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 108</u> राष्ट्रपति को हर साल कांग्रेस को संयुक्त राज्य की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहती है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को पदभार ग्रहण करने के 150 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। रिपोर्ट दो रूपों में प्रस्तुत की जाती है: उच्च सुरक्षा मंजूरी वाले अधिकारियों के लिए एक वर्गीकृत संस्करण और जनता के लिए उपलब्ध एक अवर्गीकृत संस्करण।

<u>राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) 1986</u> के रक्षा पुनर्गठन अधिनियम के गोल्डवाटर-निकोल्स विभाग की धारा 603 (सार्वजनिक कानून 99-433) द्वारा अनिवार्य एक रिपोर्ट है। एनएसएस 1987 से प्रतिवर्ष प्रसारित किया जा रहा है, लेकिन अक्सर रिपोर्ट देर से आती है या बिल्कुल नहीं आती है। कार्यकारी शाखा की राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टि को विधायी शाखा तक पहुँचाने के लिए एनएसएस को राष्ट्रपति से कांग्रेस में भेजा जाना है। एनएसएस राष्ट्र के सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अमेरिकी शक्ति के सभी पहलुओं के प्रस्तावित उपयोगों पर चर्चा प्रदान करता है। रिपोर्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय हितों, प्रतिबद्धताओं, उद्देश्यों और नीतियों के साथ-साथ खतरों को रोकने और अमेरिकी सुरक्षा योजनाओं को लागू करने के लिए आवश्यक रक्षा क्षमताओं की चर्चा शामिल करने के लिए बाध्य है।

<u>राष्ट्रीय सुरक्षा के अवधारणा की परिभाषा</u>

हेरोल्ड लैसवेल 1950, राष्ट्रीय सुरक्षा का विशिष्ट अर्थ विदेशी शासन से मुक्ति है।

अर्नोल्ड वोल्फर्स 1960, राष्ट्रीय सुरक्षा का उद्देश्य अधिग्रहीत मूल्यों के लिए खतरों की अनुपस्थिति और व्यक्तिपरक रूप से, भय की अनुपस्थिति है कि ऐसे मूल्यों पर हमला किया जाएगा।

चार्ल्स मैयर1990, राष्ट्रीय सुरक्षा ... को उन घरेलू और विदेशी परिस्थितियों को नियंत्रित करने की क्षमता के रूप में वर्णित किया गया है, जो किसी दिए गए समुदाय की जनता की राय को अपने स्वयं के निर्णय या स्वायत्तता, समृद्धि और भलाई का आनंद लेने के लिए आवश्यक मानती है।

प्रभाकरन पलेरी 2008, राज्य के सभी उपकरणों को संतुलित करके, अपने लोगों की स्पष्ट भलाई और किसी भी समय एक राष्ट्र-राज्य के रूप में इसके अस्तित्व के लिए बहु-आयामी खतरों को दूर करने के लिए एक राष्ट्र की क्षमता की औसत दर्जे की स्थिति है। शासन के माध्यम से नीति ... और इसके बाहरी चर द्वारा वैश्विक सुरक्षा के लिए विस्तार योग्य है।

<u>क्षेत्र के आधार पर भारत की स्थिति</u>

भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रमुख होता है, सभी प्रकार की खुफिया रिपोर्ट प्राप्त करता है, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर भारत के प्रधान मंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भारत के रक्षा,विदेश,गृह , वित्त मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य हैं और यह सभी पहलुओं में भारत की सुरक्षा के लिए रणनीतियों को आकार देने के लिए जिम्मेदार है। "भारत के सर्वोच्च न्यायालय" (SC) में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की। इस जनहित याचिका का जवाब देते हुए, दिल्ली पुलिस ने जुलाई 2019 में SC को बताया कि पिछले 28 महीनों में लगभग 500 अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को निर्वासित किया गया है। [44] अनुमानित 600,000 से 700,000 अवैध बांग्लादेशी औरराष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) क्षेत्र में विशेष रूप से गुरुग्राम , फरीदाबाद , और नूंह (मेवात क्षेत्र) के साथ-साथ भिवानी और हिसार के आंतरिक गांवों में रोहिंग्या अप्रवासी । उनमें से ज्यादातर मुसलमान हैं जिन्होंने नकली हिंदू पहचान हासिल की है, और पूछताछ के तहत वे पश्चिम बंगाल से होने का दिखावा करते हैं। सितंबर 2019 में, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के लिए एनआरसी लागू करने की घोषणा कीएनआरसी को अद्यतन करने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एचएस भल्ला के तहत एक कानूनी ढांचा स्थापित करके, जो इन अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालने में मदद करेगा।

<u>राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक नीति</u>

2011-2016 फिलीपींस एनएसपी ने जोर दिया कि "लोगों का कल्याण और भलाई प्राथमिक विचार है" (पृष्ठ 31, पैरा 4)। 2017-2022 फिलीपींस एनएसपी इस अवधारणा को दोहराता है, पुष्टि करता है कि "आम जनता को किसी भी नुकसान से सुरक्षित और संरक्षित किया जाना चाहिए जो उनके जीवन, संपत्तियों और जीवन के तरीकों को खतरे में डाल सकता है" (प्रि. 19, पैराग्राफ 3)।

2013 पापुआ न्यू गिनी एनएसपी "जन-केंद्रित सुरक्षा" पर जोर देता है, साथ ही साथ राज्य-केंद्रित शासनों द्वारा लाए गए सुरक्षा चिंताओं के संदर्भों को भी शामिल करता है;
2013 पेरू एनएसएस का पहला रणनीतिक उद्देश्य नागरिक सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति पर केन्द्रित है (पृष्ठ 73);

2008 लाइबेरिया एनएसएस नए सुरक्षा ढांचे को "राज्य, मानव और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के आधार पर निर्मित" करने के लिए कहता है (पृष्ठ 15, खंड 9)।

2009 बेलीज एनएसएस का लक्ष्य 6 लोकतांत्रिक शासन की संस्थाओं को मजबूत करने पर केंद्रित है (पृष्ठ 32)। इसमें सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम , सार्वजनिक आधिकारिक भ्रष्टाचार के मामलों पर सार्वजनिक सीनेट की सुनवाई, और नागरिक समाज और निजी क्षेत्र से रचनात्मक इनपुट शामिल हैं;

2015 यूनाइटेड किंगडम एनएसएस "सार्वजनिक अधिकारियों को मजबूत निगरानी, पारदर्शिता और सुरक्षा उपायों के साथ आवश्यक जांच शक्तियों को समेकित करने" के लिए प्रतिबद्ध है (पृष्ठ 38, खंड 4.90);

2013 पापुआ न्यू गिनी एनएसपी के लक्ष्य 6 में राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक संसदीय निरीक्षण समिति की स्थापना की आवश्यकता है (पृष्ठ 50);

2015 संयुक्त राज्य एनएसएस में नागरिक समाज को अपने विशिष्ट मूल्यों में से एक के रूप में सशक्त बनाना शामिल है (पृष्ठ 21)।

सुरक्षा क्षेत्र के लोकतांत्रिक निरीक्षण को एक अंतरराष्ट्रीय मानदंड के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है (अन्य के बीच संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेजों में जोर दिया गया है)। इसमें मजबूत जांच और संतुलन स्थापित करना और जवाबदेही और पारदर्शिता के सिद्धांतों को बनाए रखना शामिल है, साथ ही यह सुनिश्चित करना कि सुरक्षा प्रदाता प्रभावी ढंग से और पर्याप्त रूप से और कानूनी और नीतिगत ढांचे के अनुसार काम कर रहे हैं। निरीक्षण और उत्तरदायित्व पर एक मजबूत ध्यान एनएसएस की वैधता और स्वामित्व के लिए दृढ़ता से योगदान देता है, संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करता है, और संस्थानों की अखंडता को मजबूत करता है। एक मजबूत मानवाधिकार दृष्टिकोण समुदायों के साथ साझेदारी बनाने और सुरक्षा मुद्दों को हल करने में मदद करने के लिए उनकी लचीलापन विकसित करने के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है।

<u>सन्दर्भ</u>

- ब्रेज़ज़िंस्की, ज़िबिग्न्यू । शक्ति और सिद्धांत: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के संस्मरण, 1977-1981 । न्यूयॉर्क: फरार, स्ट्रॉस, गिरौक्स, 1983।
- चेन, सिंचुन। राष्ट्रीय सुरक्षा । एम्स्टर्डम: एल्सेवियर, 2007।
- Cordesman, एंथोनी एच सऊदी अरब: एक परेशान क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा । सांता बारबरा, कैलिफ़ोर्निया: प्रेगेर सिक्योरिटी इंटरनेशनल, 2009।
- डेवानी, जो, और जोश हैरिस, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद: सरकार के केंद्र में राष्ट्रीय सुरक्षा । लंदन: सरकार के लिए संस्थान / किंग्स कॉलेज लंदन , 2014।
- फराह, पाओलो डेविड; रॉसी, पियरकार्लो (2015)। "ऊर्जा: स्थिरता और सुरक्षा के आयामों के तहत नीति, कानूनी और सामाजिक-आर्थिक मुद्दे"। यूरेशिया और प्रशांत रिम में वैश्वीकरण पर विश्व वैज्ञानिक संदर्भ । एसएसआरएन 2695701 ।
- जॉर्डन, आमोस ए., विलियम जे. टेलर, माइकल जे. मज़ार, और सुज़ैन सी. नीलसन। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा । बाल्टीमोर, एमडी: जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999।

- मैकगवायर, माइकल। पेरेस्त्रोइका और सोवियत राष्ट्रीय सुरक्षा । वाशिंगटन डीसी: ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन प्रेस, 1991।आईएसबीएन 978-0815755531
- मुलर, कार्ल पी. स्ट्राइकिंग फर्स्ट: प्रीमेप्टिव एंड प्रिवेंटिव अटैक इन यूएस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी । सांता मोनिका, सीए: रैंड प्रोजेक्ट एयर फ़ोर्स, 2006।
- राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद (अमेरिका)। परे "किले अमेरिका": एक वैश्वीकृत दुनिया में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय सुरक्षा नियंत्रण । वाशिंगटन, डीसी: राष्ट्रीय अकादमियां प्रेस, 2009।
- नील, एंड्रयू। एक छोटे राष्ट्र में सुरक्षा: स्कॉटलैंड, लोकतंत्र, राजनीति । ओपन बुक प्रकाशक, 2017।
- रोथकोफ, डेविड जे। रनिंग द वर्ल्ड: द इनसाइड स्टोरी ऑफ़ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एंड द आर्किटेक्ट्स ऑफ़ अमेरिकन पावर । न्यूयॉर्क: पब्लिक अफेयर्स, 2005।
- रिप्समैन, नॉरिन एम, और टीवी पॉल। वैश्वीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा राज्य । ऑक्सफोर्ड: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2010।
- ताल, इज़राइल। राष्ट्रीय सुरक्षा: इजरायल का अनुभव । वेस्टपोर्ट, कॉन: प्रेगर, 2000।
- तन, एंड्रयू। मलेशिया के सुरक्षा दृष्टिकोण । कैनबरा: सामरिक और रक्षा अध्ययन केंद्र, ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय , 2002